REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 6 | MARCH - 2019

''पर्यावरण संरक्षण कानून एवं लोक स्वास्थ्य''

डॉ.राजू रैदास[1], डॉ.चन्द्रकला अरमोती[2]
[1]अतिथि विद्वान वाणिज्य शास. आर. व्ही. पी. एस(स्मृति) महा. वि. उमरिया
[2]सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) रानी दुर्गावती शास. महा. वि. मण्डला

प्रस्तावना –

औद्योगिक देशों में, स्वैच्छिक पर्यावरण समझौते अक्सर कंपनियों को न्यूनतम नियामक मानकों से आगे बढ़ने के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं और इस प्रकार सर्वोत्तम पर्यावरण अभ्यास के विकास का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में पर्यावरण सुधार ट्रस्ट (EIT) 1998 से पर्यावरण और वन संरक्षण के लिए काम कर रहा है। ग्रीन वॉलंटियर्स के एक समूह को ग्रीन इंडिया स्वच्छ भारत की अवधारणा का एक लक्ष्य मिलता है। सीए गजेंद्र कुमार जैन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सोजत शहर में भारत में राजस्थान राज्य के एक छोटे से गाँव में पर्यावरण सुधार ट्रस्ट के संस्थापक हैं, विकासशील देशों, जैसे कि लैटिन अमेरिका में, ये समझौते आमतौर पर महत्वपूर्ण स्तरों को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं अनिवार्य विनियमन के साथ गैर-अनुपालन। इन समझौतों के साथ मौजूद चुनौतियाँ आधारभूत डेटा लक्ष्य, निगरानी और रिपोर्टिंग की स्थापना में निहित हैं। प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में निहित कठिनाइयों के कारण, उनके उपयोग पर अक्सर सवाल उठाया जाता है और, वास्तव में, पूरे पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया जा सकता है। विकासशील देशों में उनके उपयोग का मुख्य लाभ यह है कि उनका उपयोग पर्यावरण प्रबंधन क्षमता बनाने में मदद करता है।

सरकारी संरक्षण :-

बायोस्फीयर का विभाजन मुख्य सरकारी निकाय है जो सुरक्षा की देखरेख करता है। यह पर्यावरण के मुद्दों, पर्यावरण नियोजन और नीति-उन्मुख पर्यावरण अनुसंधान के नीति, समन्वय और निगरानी के गठन के माध्यम से करता है। राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन परिषद (NEMC) एक संस्था है जिसे राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन अधिनियम पहली बार वर्ष 1983 में पेश किया गया था। इस परिषद में पर्यावरणीय मुद्दों पर सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सलाह देने की भूमिका है। NEMC निम्नलिखित उद्देश्य: तकनीकी सलाह प्रदान करता है; तकनीकी गतिविधियों का समन्वय; प्रवर्तन दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं विकसित करना; पर्यावरण को प्रभावित करने वाली गतिविधियों का आकलन, निगरानी और मूल्यांकन; पर्यावरण की जानकारी और संचार को बढ़ावा देना और सहायता करना; और वैज्ञानिक ज्ञान की उन्नति चाहते हैं। 1997 की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति तंजानिया में पर्यावरणीय निर्णय लेने के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करती है। नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- पर्यावरण को ख़राब किए बिना या स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे में डाले बिना संसाधनों का स्थायी और समान उपयोग सुनिश्चित करें।
- भूमि, जल, वनस्पति और वायु के क्षरण को रोकना और नियंत्रित करना

- अद्वितीय पारिस्थितिकी प्रणालियों की जैविक विविधता सहित प्राकृतिक और मानव निर्मित विरासत का संरक्षण और संवर्द्धन करें
- अपमानित क्षेत्रों की स्थिति और उत्पादकता में सुधार
- पर्यावरण और विकास के बीच की कड़ी के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाएँ
- व्यक्तिगत और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना
- पारिस्थितिक रूप से संसाधनों का उपयोग करें।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 :-

यह अधिनियम 1986 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। जैसा कि परिचय कहता है, "पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए और वहां से जुड़े मामलों के लिए एक अधिनियम प्रदान करना है जहां मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निर्णय लिए गए थे स्टॉकहोम में जून, 1972 में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने भाग लिया था, ताकि मानव पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। और जहां तक संरक्षण और सुधार से संबंधित है, वहां अब तक के निर्णयों को लागू करने के लिए इसे और भी आवश्यक माना गया है। पर्यावरण और मनुष्यों, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों और संपत्ति के लिए खतरों की रोकथाम "। यह भोपाल गैस त्रासदी के कारण था जिसे भारत में सबसे खराब औद्योगिक त्रासदी माना जाता था।

भोपाल त्रासदी के मद्देनजर, भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया। मार्च 1986 में पारित, यह 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। इसके 26 खंड हैं। अधिनियम का उद्देश्य मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना है। वे मानव पर्यावरण के संरक्षण और सुधार और मानव के लिए खतरों की रोकथाम, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों और संपत्ति से संबंधित हैं। अधिनियम एक "छाता" कानून है जिसे पिछले कानूनों के तहत स्थापित विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों की गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार के समन्वय के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि जल अधिनियम और वायु अधिनियम।

भारत में, पर्यावरण संरक्षण कानून पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 द्वारा शासित है। यह अधिनियम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा लागू किया गया है।इसके अलावा, विशेष रूप से जल, वायु, वन्यजीवों आदि के संरक्षण के लिए अलग-अलग विधान भी बनाए गए हैं, ऐसे विधान सभाओं में शामिल हैं: -

- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- द वाटर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) सेस एक्ट, 1977
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- वायु (रोकथाम और प्रदूषण का नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- वायु (रोकथाम और प्रदूषण पर नियंत्रण) (केंद्र शासित प्रदेश) नियम, 1983
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, 1972
- बैटरियों (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2001
- पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक, प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम, 1999

- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2010 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत स्थापित किया, जिसमें सभी पर्यावरणीय मामलों पर एक पर्याप्त पर्यावरणीय प्रश्न और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत कार्य करता है।
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर नियम, 1978
- गंगा एक्शन प्लान, 1986
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
- सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 और जैविक विविधता अधिनियम, 2002। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शामिल अधिनियम राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। अपील भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है।
- खतरनाक कचरे और उनके निपटान, 1989 और इसके प्रोटोकॉल पर ट्रांसबाउंडरी मोमेंट्स के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन
- खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रबंधन) संशोधन नियम, 2003

सार्वजनिक स्वास्थ्य : -

सार्वजनिक स्वास्थ्य "रोग को रोकने, जीवन को लंबा करने और संगठित प्रयासों और समाज, संगठनों, सार्वजनिक और निजी, समुदायों और व्यक्तियों के सूचित विकल्पों के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का विज्ञान और कला है"। जनसंख्या के स्वास्थ्य और खतरों का विश्लेषण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आधार है। विचाराधीन "जनता" मुट्ठी भर लोगों की तरह छोटा हो सकता है, एक पूरा गाँव या यह महामारी के मामले में कई महाद्वीपों जितना बड़ा हो सकता है। "स्वास्थ्य" शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, यह केवल बीमारी या दुर्बलता का अभाव नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अंतःविषय है । उदाहरण के लिए, महामारी विज्ञान , जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवाएं सभी प्रासंगिक हैं। पर्यावरणीय स्वास्थ्य , सामुदायिक स्वास्थ्य , व्यवहार स्वास्थ्य , स्वास्थ्य अर्थशास्त्र , सार्वजनिक नीति , मानसिक स्वास्थ्य और व्यावसायिक सुरक्षा , स्वास्थ्य में लैंगिक मुद्दे, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अन्य महत्वपूर्ण उपक्षेत्र हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सहित रोग की रोकथाम और उपचार के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह मामलों और स्वास्थ्य संकेतकों की निगरानी के माध्यम से, और स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देने के माध्यम से किया जाता है। सामान्य सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में हस्त - मैथुन और स्तनपान को बढ़ावा देना, टीकाकरण का वितरण, आत्महत्या की रोकथाम और यौन संचारित रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कंडोम का वितरण शामिल है ।

आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभ्यास के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और पेशेवरों कीबहु-विषयक टीमों की आवश्यकता होती है। टीमों में एपिडेमियोलॉजिस्ट , बायोस्टैटिस्ट , मेडिकल असिस्टेंट , पब्लिक हेल्थ नर्स , मिडवाइव्स , मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, आनुवंशिकीविद् और डेटा मैनेजर शामिल हो सकते हैं। जरूरत के आधार पर पर्यावरणीय स्वास्थ्य अधिकारी या सार्वजनिक स्वास्थ्य निरीक्षक , बायोएथिसिस्ट और यहां तक कि पशु चिकित्सक , लिंग विशेषज्ञ, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य विशेषज्ञ को बुलाया जा सकता है।

स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल की पहुंचविकासशील देशों में कठिन चुनौतियां हैं । सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचनाएं अभी भी उन देशों में बन रही हैं। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र , संयुक्त राज्य अमेरिका के उप सचिव के साथ मिलकर काम करता है। सात मूल सिद्धांत हैं: -

1. महिलाओं, लड़कियों और लैंगिक समानता
2. रणनीतिक समन्वय और एकीकरण
3. प्रमुख बहु पक्षीय और अन्य साझेदारों को मजबूत और उत्तोलन करना
4. देश-स्वामित्व
5. स्वास्थ्य प्रणालियों के माध्यम से स्थिरता
6. मैट्रिक्स, निगरानी और मूल्यांकन में सुधार करें
7. अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना

सेनेटरी सुधार और जन स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना के पहले प्रयास 1840 के दशक में किए गए थे। लंदन फेवर अस्पताल के चिकित्सकथॉमस साउथवुड स्मिथने स्वास्थ्य के महत्व पर पत्र लिखना शुरू किया, और 1830 के दशक में नील अर्नोट और जेम्स फिलिप्स के साथ गरीब कानून आयोग के सामने साक्ष्य देने के लिए पहले चिकित्सकों में से एक थे। के । स्मिथ ने हैजा और पीत ज्वर की तरह संक्रामक रोगों के प्रसार को सीमित करने के लिए संगरोध और स्वच्छता सुधार के महत्व पर सरकार को सलाह दी । सहायता प्रभावशीलता एजेंडा इन बड़े पैमाने के कार्यक्रमों जैसे किएड्स से लड़ने के लिए ग्लोबल फंड, ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया और वैक्सीन के लिए ग्लोबल एलायंस और टीकाकरण (जीएवीआई) के प्रभाव को मापने के लिए एक उपयोगी उपकरण है जो तेजी से और दृश्यमान परिणाम प्राप्त करने में सफल रहे हैं। ग्लोबल फंड का दावा है कि उसके प्रयासों ने दुनिया भर में तीन मिलियन से अधिक लोगों को एंटीरेट्रोवायरल उपचार प्रदान किया है। जीएवीआई का दावा है कि उसके टीकाकरण कार्यक्रमों ने २००० में शुरू होने के बाद से ५ मिलियन से अधिक मौतों को रोका है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. नव भारत पत्रिका वर्ष 2017
2. पत्रिका समाचार पत्र, जबलपुर संस्करण फरवरी 2018
3. www.google.com/wikipedia.com
4. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986
5. ''पर्यावरण कानून'' द स्टेट्समैन, 19 जनवरी 2017
6. विश्व स्वास्थ्य संगठन (2000) विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट 2000

डॉ.राजू रैदास
अतिथि विद्वान वाणिज्य शास. आर. व्ही. पी. एस (स्मृति) महा.वि.उमरिया.

डॉ.चन्द्रकला अरमोती
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) रानी दुर्गावती शास. महा. वि. मण्डला.